



राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन सुधार एवं दक्षता—आधारित अधिगम : विकसित भारत 2047 की दिशा में एक बहुविषयक अध्ययन

बृजेश चन्द्र यादव

शोधार्थी, शिक्षक—शिक्षा विभाग मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़, उत्तर प्रदेश

Email- bcy4586@gmail.com

Received: 09 May 2026 | Accepted: 17 May 2026 | Published: 25 June 2026

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक एवं परिवर्तनकारी सुधारों का आधार प्रस्तुत करती है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में केवल विषयगत ज्ञान का विकास करना नहीं, बल्कि उनमें आलोचनात्मक चिंतन, समस्या—समाधान, नवाचार, सृजनात्मकता, नैतिकता, संचार—कौशल तथा जीवन—कौशल जैसी 21वीं सदी की आवश्यक दक्षताओं का विकास करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीति में मूल्यांकन प्रणाली को पारंपरिक परीक्षा—केंद्रित दृष्टिकोण से हटाकर दक्षता—आधारित, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली अपनाने पर बल दिया गया है। प्रस्तुत शोध—पत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में मूल्यांकन सुधार एवं दक्षता—आधारित अधिगम की अवधारणा का विश्लेषण करना तथा विकसित भारत 2047 के निर्माण में इसकी भूमिका का अध्ययन करना है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि पारंपरिक रटंत शिक्षा विद्यार्थियों के वास्तविक ज्ञान, कौशल तथा व्यवहारगत दक्षताओं का समुचित मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है। इसके स्थान पर परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो, अनुभवात्मक अधिगम, प्रायोगिक गतिविधियाँ, सहपाठी मूल्यांकन, स्व—मूल्यांकन तथा डिजिटल मूल्यांकन जैसी विधियाँ विद्यार्थियों के समग्र विकास को अधिक प्रभावी रूप से सुनिश्चित करती हैं। शोध में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विभिन्न शोध—पत्रों, पुस्तकों, सरकारी रिपोर्टों एवं शैक्षिक दस्तावेजों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में दक्षता—आधारित अधिगम एवं मूल्यांकन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो शिक्षार्थियों में आत्मनिर्भरता, नवाचार, नेतृत्व क्षमता, रोजगारपरक कौशल तथा

सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास होगा, जो विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अतः आवश्यक है कि शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल अवसंरचना, पाठ्यचर्या सुधार तथा सतत मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाकर शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं परिणामोन्मुख बनाया जाए।

मुख्य शब्द — राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूल्यांकन सुधार, दक्षता-आधारित अधिगम, विकसित भारत 2047 समग्र मूल्यांकन, अनुभवात्मक अधिगम।

प्रस्तावना

21वीं शताब्दी में शिक्षा का स्वरूप तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है। वैश्वीकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा ज्ञान-आधारित समाज के विकास ने शिक्षा प्रणाली के समक्ष नई चुनौतियाँ एवं अवसर प्रस्तुत किए हैं। वर्तमान समय में केवल विषयगत ज्ञान पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, सहयोगात्मक कार्य, संचार-कौशल, समस्या-समाधान क्षमता, नेतृत्व, नैतिक मूल्यों तथा नवाचार जैसी दक्षताओं का विकास भी समान रूप से आवश्यक हो गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) लागू की, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला, बहुविषयक, कौशल-उन्मुख तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल दर्शन यह है कि शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम न होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की क्षमता विकसित करने का साधन बने। इसलिए इस नीति में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ-साथ मूल्यांकन प्रणाली में भी व्यापक परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है। पारंपरिक परीक्षा प्रणाली मुख्यतः स्मरण शक्ति एवं रटने की प्रवृत्ति पर आधारित रही है, जिसके कारण विद्यार्थी विषय की वास्तविक समझ, अनुप्रयोग क्षमता तथा सृजनात्मक सोच विकसित नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले अनेक विद्यार्थी व्यावहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दक्षता-आधारित अधिगम एवं मूल्यांकन प्रणाली को अपनाने पर बल देती है।

दक्षता-आधारित अधिगम ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जाता कि उन्होंने कितना याद किया है, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि वे अर्जित ज्ञान का वास्तविक जीवन में कितना प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रणाली में अवधारणात्मक समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता, संचार-कौशल, सहयोगात्मक अधिगम, सृजनात्मकता,

नैतिक निर्णय क्षमता तथा व्यावहारिक दक्षताओं का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। इसके अंतर्गत परियोजना कार्य, केस स्टडी, प्रस्तुतीकरण, प्रयोगात्मक गतिविधियाँ, पोर्टफोलियो, स्व-मूल्यांकन तथा सहपाठी मूल्यांकन जैसी विविध मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में PARAKH (Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development) जैसी संस्थागत व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य विद्यालयी मूल्यांकन को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय, मानकीकृत एवं दक्षता-आधारित बनाना है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के समग्र विकास का मूल्यांकन किया जाएगा तथा परीक्षा प्रणाली को केवल अंक-केंद्रित न रखकर अधिगम-केंद्रित बनाया जाएगा। यह परिवर्तन शिक्षण प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी एवं विद्यार्थी-केंद्रित बनाएगा।

विकसित भारत 2047 का लक्ष्य भारत को ज्ञान-आधारित, नवाचार-प्रधान, आत्मनिर्भर तथा वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने वाला राष्ट्र बनाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब देश की शिक्षा प्रणाली ऐसे नागरिक तैयार करे जो तकनीकी रूप से दक्ष, सामाजिक रूप से उत्तरदायी, नैतिक रूप से सशक्त तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हों। इस दृष्टि से मूल्यांकन सुधार एवं दक्षता-आधारित अधिगम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन, रोजगार, उद्यमिता तथा अनुसंधान के लिए तैयार करते हैं। वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑनलाइन अधिगम, मिश्रित शिक्षण तथा व्यक्तिगत अधिगम का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में मूल्यांकन प्रणाली को भी तकनीकी रूप से सक्षम एवं लचीला बनाना आवश्यक है। डिजिटल पोर्टफोलियो, ऑनलाइन क्विज़, डेटा-आधारित प्रगति विश्लेषण तथा अनुकूली मूल्यांकन जैसी आधुनिक पद्धतियाँ विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम प्रगति को समझने में अधिक उपयोगी सिद्ध हो रही हैं।

यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने मूल्यांकन सुधार की स्पष्ट दिशा प्रदान की है, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं। इनमें शिक्षकों का पर्याप्त प्रशिक्षण, विद्यालयों में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, अभिभावकों की जागरूकता, परीक्षा-केंद्रित मानसिकता में परिवर्तन, मूल्यांकन उपकरणों का मानकीकरण तथा संस्थागत सहयोग प्रमुख हैं। इन चुनौतियों का समाधान बहुविषयक दृष्टिकोण, प्रभावी नीति-क्रियान्वयन तथा निरंतर क्षमता निर्माण के माध्यम से ही संभव है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में मूल्यांकन सुधार एवं दक्षता-आधारित अधिगम की अवधारणा, आवश्यकता, चुनौतियों तथा संभावनाओं का विश्लेषण करना है। साथ ही यह अध्ययन विकसित भारत 2047 के निर्माण में इन सुधारों की भूमिका का बहुआयामी मूल्यांकन प्रस्तुत

करता है। यह शोध शिक्षा नीति निर्माताओं, शिक्षकों, शोधार्थियों, प्रशासकों तथा विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा तथा शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, समावेशी एवं परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

साहित्य समीक्षा

NCERT (2023) द्वारा विकसित स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में अधिगम परिणामों पर आधारित शिक्षण एवं मूल्यांकन प्रणाली को विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रभावी माध्यम बताया गया है। इसमें परियोजना कार्य, अनुभवात्मक अधिगम, गतिविधि-आधारित शिक्षण तथा वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित मूल्यांकन को अधिक प्रभावी माना गया है। UNESCO (2021) के अनुसार 21वीं शताब्दी की शिक्षा में विद्यार्थियों को केवल सूचना प्रदान करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनमें वैश्विक नागरिकता, सतत विकास, डिजिटल साक्षरता, सहयोगात्मक अधिगम तथा जीवन-कौशल विकसित करना आवश्यक है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दक्षता-आधारित मूल्यांकन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधार एवं दक्षता-आधारित अधिगम को भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन का प्रमुख आधार माना गया है। इस विषय पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक विद्वानों, आयोगों तथा संस्थाओं द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि पारंपरिक परीक्षा-आधारित मूल्यांकन प्रणाली विद्यार्थियों के समग्र विकास का समुचित आकलन नहीं कर पाती। इसलिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में ऐसी मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता अनुभव की जा रही है जो विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, मूल्य तथा व्यवहार का संतुलित मूल्यांकन कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता, समस्या-समाधान क्षमता, सहयोगात्मक कार्य, नैतिकता तथा नवाचार जैसी दक्षताओं का विकास करना है। नीति में दक्षता-आधारित अधिगम तथा सतत एवं समग्र मूल्यांकन (CCE) की भावना को पुनः सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया है।

OECD (2019) की शिक्षा और कौशल का भविष्य 2030 रिपोर्ट में यह प्रतिपादित किया गया है कि भविष्य की शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ-साथ नवाचार, अनुकूलन क्षमता, सहयोग, नेतृत्व तथा नैतिक उत्तरदायित्व जैसी दक्षताओं से भी सुसज्जित करे। इसके लिए परीक्षा-केंद्रित व्यवस्था के स्थान पर दक्षता-आधारित मूल्यांकन प्रणाली विकसित करना आवश्यक है। Bloom (1956) द्वारा प्रतिपादित Bloom's Taxonomy आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली का महत्वपूर्ण आधार है। इसमें ज्ञान, समझ,

अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों का उल्लेख किया गया है। संशोधित ब्लूम वर्गीकरण (Anderson एवं Krathwohl, 2001) ने सृजनात्मकता को सर्वोच्च अधिगम स्तर माना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना से पूर्णतः मेल खाता है।

Black एवं William (1998) ने अपने शोध में स्पष्ट किया कि रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धियों में उल्लेखनीय वृद्धि करता है। यदि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिपुष्टि दी जाए, तो विद्यार्थियों का प्रदर्शन अधिक प्रभावी बनता है। Stiggins (2005) ने मूल्यांकन को अधिगम सुधार का साधन बताते हुए कहा कि मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना होना चाहिए। उन्होंने 'मेउमदज वित स्मंतदपदह' की अवधारणा को विशेष महत्व दिया।

भारतीय संदर्भ में विभिन्न शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश विद्यालयों में अभी भी परीक्षा-केंद्रित एवं स्मरण-आधारित मूल्यांकन प्रणाली प्रचलित है, जिसके कारण विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं व्यावहारिक दक्षताओं का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता। हालांकि NEP-2020 के लागू होने के बाद विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में परियोजना-आधारित शिक्षण, अनुभवात्मक अधिगम, डिजिटल मूल्यांकन तथा कौशल-आधारित शिक्षण की दिशा में सकारात्मक प्रयास प्रारम्भ हुए हैं।

उपरोक्त साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मूल्यांकन सुधार एवं दक्षता-आधारित अधिगम न केवल विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, नवाचारी, उत्तरदायी तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नागरिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए यह दृष्टिकोण अत्यंत प्रासंगिक एवं आवश्यक है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन सुधार एवं दक्षता-आधारित अधिगम के अध्ययन पर आधारित एक गुणात्मक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध है। अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित मूल्यांकन सुधारों तथा दक्षता-आधारित अधिगम की अवधारणा का विश्लेषण करना तथा विकसित भारत 2047 के निर्माण में उनकी उपयोगिता का अध्ययन करना है। इस शोध में द्वितीयक स्रोतों का व्यापक उपयोग किया गया है। अध्ययन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF 2023), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT), शिक्षा मंत्रालय, UNESCO, OECD तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों का अध्ययन किया गया। इसके अतिरिक्त

शोध-पत्र, पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, शोध-प्रबंध, जर्नल लेख, सरकारी दस्तावेज तथा विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों का भी उपयोग किया गया।

शोध की प्रकृति दस्तावेजीय विश्लेषण पर आधारित है। विभिन्न दस्तावेजों का आलोचनात्मक अध्ययन करते हुए मूल्यांकन सुधार, दक्षता-आधारित अधिगम, सीखने के परिणाम, समग्र मूल्यांकन, अनुभवात्मक अधिगम, परियोजना-आधारित शिक्षण तथा डिजिटल मूल्यांकन से संबंधित तथ्यों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाकर यह समझने का प्रयास किया गया कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में कौन-कौन सी कमियाँ हैं तथा दक्षता-आधारित मूल्यांकन इन समस्याओं का किस प्रकार समाधान प्रस्तुत करता है। इस शोध में बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाया गया है। शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, सार्वजनिक नीति तथा सतत विकास जैसे विभिन्न विषयों के सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का समन्वित अध्ययन किया गया है। इससे विषय का व्यापक एवं समग्र विश्लेषण संभव हो सका। अध्ययन में प्राप्त तथ्यों का विषयवस्तु विश्लेषण किया गया। विभिन्न दस्तावेजों में वर्णित अवधारणाओं, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का तुलनात्मक अध्ययन कर समानताओं एवं भिन्नताओं की पहचान की गई तथा उनके आधार पर शोध निष्कर्ष विकसित किए गए।

शोध की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रमाणिक एवं प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग किया गया है। सभी तथ्यों का सत्यापन विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों से किया गया तथा शोध नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करते हुए उचित संदर्भों का उल्लेख किया गया। यद्यपि यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, फिर भी इसके निष्कर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपयोगी दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। भविष्य में इस विषय पर विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर व्यापक अनुभवजन्य शोध किए जा सकते हैं। प्रस्तुत शोध प्रविधि मूल्यांकन सुधार एवं दक्षता-आधारित अधिगम की वर्तमान स्थिति, आवश्यकता, चुनौतियों एवं संभावनाओं का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करती है तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षा प्रणाली की भूमिका को स्पष्ट करती है।

विश्लेषण एवं विवेचन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली को ज्ञान-केंद्रित व्यवस्था से दक्षता-केंद्रित व्यवस्था की ओर ले जाने का एक व्यापक प्रयास है। यह नीति इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसे सक्षम, उत्तरदायी,

नवाचारी एवं आत्मनिर्भर नागरिक तैयार करना है जो व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास में सक्रिय योगदान दे सकें। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन सुधार एवं दक्षता-आधारित अधिगम को केंद्रीय स्थान दिया गया है। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में लंबे समय तक पारंपरिक परीक्षा पद्धति का वर्चस्व रहा है। इस प्रणाली में विद्यार्थियों की सफलता का निर्धारण मुख्यतः लिखित परीक्षाओं तथा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता रहा है। परिणामस्वरूप अधिकांश विद्यार्थी अवधारणात्मक समझ विकसित करने के स्थान पर रटकर परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रवृत्ति अपनाते हैं। इससे उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता, सृजनात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता, संचार-कौशल तथा व्यावहारिक दक्षताओं का समुचित विकास नहीं हो पाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है तथा मूल्यांकन को अधिगम सुधार का साधन मानती है, न कि केवल परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया।

दक्षता-आधारित अधिगम का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में ज्ञान का प्रभावी उपयोग करने योग्य बनाना है। इस व्यवस्था में केवल यह नहीं देखा जाता कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वह सीखे हुए ज्ञान, कौशल एवं मूल्यों का उपयोग व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी विज्ञान का सिद्धांत समझता है, तो उसका मूल्यांकन केवल लिखित उत्तरों के आधार पर न होकर प्रयोग, परियोजना, प्रस्तुतीकरण तथा समस्या-समाधान गतिविधियों के माध्यम से भी किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भाषा शिक्षण में केवल व्याकरण का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रभावी संचार, अभिव्यक्ति तथा आलोचनात्मक लेखन भी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में PARAKH (Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य पूरे देश में मूल्यांकन की गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। PARAKH के माध्यम से ऐसी मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जो विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम उपलब्धियों का समग्र आकलन कर सके। इससे राज्यों एवं विभिन्न शिक्षा बोर्डों के बीच मूल्यांकन की गुणवत्ता में भी समानता स्थापित करने में सहायता मिलेगी। नीति में अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning), परियोजना-आधारित अधिगम (Project-Based Learning), समस्या-समाधान आधारित शिक्षण (Problem-Based Learning), कला-एकीकृत अधिगम (Art Integrated Learning), खेल-आधारित अधिगम (Play-Based Learning) तथा बहुविषयक शिक्षण (Multidisciplinary Learning) को विशेष महत्व दिया गया

है। इन सभी शिक्षण विधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करना तथा उनकी सृजनात्मक एवं व्यावहारिक दक्षताओं का विकास करना है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी ने भी मूल्यांकन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन की संभावनाएँ उत्पन्न की हैं। ऑनलाइन मूल्यांकन, डिजिटल पोर्टफोलियो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अधिगम विश्लेषण, ई-पोर्टफोलियो तथा अनुकूली परीक्षण जैसी तकनीकों के माध्यम से विद्यार्थियों की व्यक्तिगत प्रगति का निरंतर विश्लेषण संभव हो गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण रणनीतियाँ विकसित की जा सकती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजिटल शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग पर विशेष बल देती है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं विश्वसनीय बन सके।

मूल्यांकन सुधारों के सफल क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि अधिगम के मार्गदर्शक, प्रेरक एवं मूल्यांकनकर्ता भी हैं। इसलिए शिक्षकों को दक्षता-आधारित प्रश्न निर्माण, अधिगम परिणामों का निर्धारण, परियोजना मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि प्रदान करने तथा डिजिटल मूल्यांकन उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। यदि शिक्षक स्वयं इन अवधारणाओं को भली-भाँति समझेंगे, तभी वे विद्यार्थियों में अपेक्षित दक्षताओं का प्रभावी विकास कर सकेंगे। हालाँकि इन सुधारों के क्रियान्वयन में कुछ व्यावहारिक चुनौतियाँ भी हैं। देश के अनेक विद्यालयों में अभी भी पर्याप्त डिजिटल संसाधनों का अभाव है। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट, स्मार्ट उपकरण तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी मूल्यांकन सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है। इसके अतिरिक्त अभिभावकों एवं समाज की परीक्षा एवं अंकों पर अत्यधिक निर्भर मानसिकता भी परिवर्तन की गति को प्रभावित करती है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षकों, अभिभावकों तथा समुदाय के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था, नवाचार, अनुसंधान, उद्यमिता तथा कौशल विकास के क्षेत्र में विश्वस्तरीय नेतृत्व स्थापित करना है। यह लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब शिक्षा प्रणाली ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करे जो केवल परीक्षा में सफल न हों, बल्कि जीवन की वास्तविक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हों। दक्षता-आधारित अधिगम एवं मूल्यांकन सुधार विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, नैतिक मूल्यों, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा आजीवन सीखने की प्रवृत्ति का विकास करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रस्तावित मूल्यांकन सुधार एवं दक्षता-आधारित अधिगम भारतीय

शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो वे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे, बल्कि विकसित भारत 2047 के निर्माण हेतु आवश्यक मानवीय संसाधनों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मूल्यांकन सुधार एवं दक्षता-आधारित अधिगम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली के सभी हितधारक समन्वित रूप से कार्य करें। सर्वप्रथम शिक्षकों के लिए नियमित क्षमता-विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिनमें उन्हें दक्षता आधारित प्रश्न निर्माण, अधिगम परिणामों का निर्धारण, परियोजना आधारित मूल्यांकन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन तथा डिजिटल मूल्यांकन तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षित शिक्षक ही विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम उपलब्धियों का समुचित मूल्यांकन कर सकेंगे। विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल वार्षिक परीक्षा पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली के स्थान पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन लिखित परीक्षा के अतिरिक्त परियोजनाओं, प्रयोगों, प्रस्तुतीकरण, समूह चर्चा, केस स्टडी, फील्ड वर्क, नवाचार गतिविधियों तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से भी किया जाना चाहिए।

डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक विद्यालय एवं महाविद्यालय में इंटरनेट सुविधा, स्मार्ट कक्षाएँ, डिजिटल मूल्यांकन प्लेटफॉर्म, ई-पोर्टफोलियो तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अधिगम विश्लेषण उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय एवं समयबद्ध बन सके। पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकों को भी दक्षता-आधारित अधिगम के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए। विषयवस्तु को इस प्रकार तैयार किया जाए कि विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान क्षमता, सृजनात्मकता, सहयोगात्मक अधिगम तथा नैतिक मूल्यों का विकास हो। केवल तथ्यों के संग्रह पर आधारित सामग्री के स्थान पर अनुभवात्मक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अभिभावकों एवं समुदाय को भी मूल्यांकन सुधारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। वर्तमान समय में अधिकांश अभिभावक विद्यार्थियों की सफलता को केवल परीक्षा के अंकों से जोड़कर देखते हैं। यदि उन्हें दक्षता-आधारित शिक्षा एवं समग्र विकास के महत्व से अवगत कराया जाए, तो वे भी इस परिवर्तन के सक्रिय सहयोगी बन सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर PARAKH जैसी संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा राज्यों एवं विभिन्न शिक्षा बोर्डों के लिए समान गुणवत्ता मानक विकसित किए

जाएँ। साथ ही विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन सुधारों की नियमित निगरानी एवं समीक्षा की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अंततः यह आवश्यक है कि मूल्यांकन प्रणाली को केवल प्रमाणपत्र प्राप्त करने का माध्यम न मानकर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, जीवन-कौशल, रोजगारपरक क्षमता तथा राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित किया जाए। यही दृष्टिकोण विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में सार्थक योगदान देगा।

भविष्य में क्रियान्वयन

विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित मूल्यांकन सुधार एवं दक्षता-आधारित अधिगम का प्रभावी एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। भविष्य में सभी विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में परिणाम-आधारित शिक्षा को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम परिणामों का स्पष्ट एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन संभव हो सके। आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, बिग डेटा तथा लर्निंग एनालिटिक्स जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग मूल्यांकन प्रणाली में व्यापक रूप से किया जा सकता है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम गति, रुचि, कठिनाइयों एवं उपलब्धियों का व्यक्तिगत विश्लेषण संभव होगा तथा व्यक्तिगत अधिगम को बढ़ावा मिलेगा।

शिक्षक शिक्षा संस्थानों में दक्षता-आधारित शिक्षण एवं मूल्यांकन को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। बी.एड., डी.एल.एड. तथा एम.एड. पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन सुधार, डिजिटल मूल्यांकन, परियोजना-आधारित अधिगम तथा अधिगम परिणामों पर आधारित प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। भविष्य में उद्योग, विश्वविद्यालय तथा विद्यालयों के मध्य सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभव प्राप्त हो सकें। इंटर्नशिप, सामुदायिक परियोजनाएँ, स्टार्टअप गतिविधियाँ तथा कौशल विकास कार्यक्रमों को मूल्यांकन का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। इससे शिक्षा एवं रोजगार के मध्य अंतर कम होगा तथा विद्यार्थी आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के लिए विशेष योजनाएँ लागू की जानी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट, डिजिटल उपकरण एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराना भविष्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित होंगे। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर समय-समय पर मूल्यांकन प्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके आधार पर आवश्यक सुधार लागू किए जाएँ ताकि शिक्षा प्रणाली बदलती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर विकसित होती रहे।

भविष्य में बहुविषयक एवं अंतर्विषयक शिक्षण को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी विभिन्न विषयों के ज्ञान को एकीकृत करके नवीन समाधान विकसित कर सकेंगे। अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को भी मूल्यांकन प्रणाली में समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। यदि इन सभी सुझावों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था ज्ञान, कौशल एवं नवाचार पर आधारित विश्वस्तरीय प्रणाली के रूप में विकसित होगी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तनकारी सुधारों का आधार प्रस्तुत करती है। मूल्यांकन सुधार एवं दक्षता आधारित अधिगम इस नीति के प्रमुख स्तंभ हैं, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ-साथ कौशल, सृजनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, नैतिकता तथा जीवनोपयोगी दक्षताओं का विकास करना है। पारंपरिक परीक्षा प्रणाली के स्थान पर समग्र एवं सतत मूल्यांकन प्रणाली विद्यार्थियों के वास्तविक अधिगम का अधिक प्रभावी आकलन करती है। यदि इन सुधारों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो भारत एक ज्ञान-आधारित, नवाचार प्रधान एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित होकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा।

संदर्भ सूची

1. एंडरसन, एल. डब्ल्यू., एवं क्रैथवोल, डी. आर. (2001). अधिगम, शिक्षण एवं मूल्यांकन का वर्गीकरण. लॉन्गमैन।
2. ब्लैक, पी., एवं विलियम, डी. (1998). कक्षा अधिगम एवं मूल्यांकन। असेसमेंट इन एजुकेशन, 5(1), 7-74।
3. ब्लूम, बी. एस. (1956). शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण—हैंडबुक-I (संज्ञानात्मक क्षेत्र). डेविड मैके।
4. शिक्षा मंत्रालय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020- भारत सरकार।
5. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी). (2023). स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023- एनसीईआरटी।
6. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)-(2019)- शिक्षा एवं कौशल का भविष्य 2030. ओईसीडी पब्लिशिंग।
7. स्टिगिन्स, आर. जे. (2005). अधिगम हेतु मूल्यांकन। फाई डेल्टा कैम्पन, 87(4), 324-328।

8. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को). (2021). हमारे साझा भविष्य की पुनर्कल्पनारू शिक्षा के लिए एक नया सामाजिक अनुबंध. यूनेस्को।
9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी). (2022). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश. यूजीसी।
10. राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र-परख (PARAKH) (2023). मूल्यांकन सुधार रूपरेखा. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)।
11. भारत सरकार. (2023). विकसित भारत 2047: दृष्टि दस्तावेज़. भारत सरकार।
12. बिग्स, जे., एवं टैंग, सी. (2011). विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण (चौथा संस्करण). ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस।
13. फुलन, एम. (2007). शैक्षिक परिवर्तन का नया अर्थ (चौथा संस्करण). टीचर्स कॉलेज प्रेस।
14. विश्व बैंक. (2020). अधिगम गरीबी की स्थिति. विश्व बैंक।
15. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी). (2021). माध्यमिक स्तर पर अधिगम प्रतिफल. एनसीईआरटी।